रणजीत टाइम्स

इंदौर

गुरुवार, 21 अगस्त, 2025

वर्ष 01 | अंक 209 | कुल पृष्ठ : 8 | Digital

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

वादे हवा हो गए

ग्राम

पानोद में कटी कॉलोनी, सिल्वर पार्क और साईं गोल्ड सिटी के रहवासी बेहाल

इंदौर। साल 2010–12 के दौरान जिन कॉलोनियों को "आधुनिक सुविधाओं से लैस सपनों का आशियाना" बताकर प्लॉट बेचे गए थे, वे आज बदहाली की मिसाल बनी हुई हैं।

दीपक वाड़ेकर

इंदौर। कट्टी कॉलोनी, सिल्वर पार्क और साईं गोल्ड सिटी में रहने वाले सैकड़ों परिवार आज भी टूटी और गड्ढों से भरी सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। बरसात आते ही हालात और भयावह हो जाते हैं।

जगह-जगह पानी भरने से कीचड़ और फिसलन बढ़ जाती है। स्ट्रीट लाइट्स न होने के कारण महिलाएँ, बच्चे और बुजुर्ग हर रोज़ अंधेरे में अपनी सुरक्षा को लेकर डरते हैं। कई लोग तो मजबूरी में गाड़ियों से आते-जाते हैं, लेकिन दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है।

जिम्मेदारी का खेल

डेवलपर्स – जिन्होंने बड़े-बड़े वादे किए लेकिन मूलभूत सुविधाएँ पूरी नहीं कीं।

ग्राम पंचायत/नगर निगम – जिन्होंने आज तक सुधार की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए।

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग – जिसने कॉलोनी का नक्शा पास करने के बाद विकास की निगरानी नहीं की।

निवासियों की पुकार

स्थानीय लोगों का कहना है कि अब उनका सब्र जवाब दे चुका है। रोज़ाना जान जोखिम में डालकर आवागमन करना उनकी मजबूरी है। वे मांग कर रहे हैं कि प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप करे और डेवलपर्स को उनके वादों के लिए जवाबदेह ठहराए।

रणजीत टाइम्स यह सवाल उठाता है

"कब तक इंदौर की कॉलोनियों में लोग अधूरे वादों और बदहाल सड़कों के बीच जीने को मजबूर रहेंगे?"

NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक बने। नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद थे।

भोपाल। मुख्यमंत्री निवास मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव , भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खण्डेलवाल तथा प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद शर्मा की उपस्थिति में आज बुधवार को एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक बैठक संपन्न हुई।

गजब! ग्वालियर-दिल्ली में बताई जा रही अर्चना तिवारी भारत-नेपाल बॉर्डर पर मिली...

ग्वालियर के आरक्षक परमार की गिरफ्तारी के बाद से चर्चा में आई अर्चना तिवारी को लेकर तरह-तरह की सूचनाएँ सामने आती रहीं। पहले कहा गया कि उसकी तलाशी में एक टीम ग्वालियर पहुंची है, फिर दोपहर में यह खबर भी आई कि उसकी मोबाइल लोकेशन दिल्ली में मिली है और उसे पकड़ने के लिए टीम दिल्ली रवाना हो चुकी है। लेकिन इस बीच भोपाल जीआरपी थाना रानी कमलापति की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की। एसआरपी भोपाल राहुल कुमार लोढा ने पुष्टि की कि अर्चना तिवारी को भारत-नेपाल सीमा पर उत्तरप्रदेश के लखीमपुर जिले से पकड़ लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, अर्चना ने अपनी माँ से बातचीत में अपनी लोकेशन बताई थी, जिसके आधार पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुँची और उसे हिरासत में ले लिया। अब पुलिस अर्चना से पूछताछ कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आखिर उसका ग्वालियर आरक्षक परमार से क्या रिश्ता है और वह सीमा क्षेत्र तक कैसे पहुँची।

इंदौर बनेगा सतत विकास का ग्लोबल मॉडल

नगर निगम और UNAccc के बीच 21 अगस्त को एमओयू बीपीएल परिवारों के लिए सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोग्राम, ऊर्जा व ईंधन खर्च में 30% तक की बचत का लक्ष्य

इंदौर। स्वच्छता और नवाचार की दिशा में लगातार नए आयाम स्थापित करने वाला इंदौर अब सतत विकास और क्लाइमेट एक्शन का वैश्विक मॉडल बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। आगामी 21 अगस्त को नगर पालिक निगम, इंदौर और यूनाइटेड नेशन एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज काउंसिल (UNAccc) के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन होगा। यह कार्यक्रम गुरुवार को सुबह 10 बजे जाल सभा गृह में आयोजित किया जाएगा। इस एमओयू का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के L.I.F.E. मिशन, स्वच्छ भारत सर्टिफिकेशन और सस्टेनेबल हाउसिंग मिशन नेट जीरो के अनुरूप पहल को आगे बढ़ाना है। इसके तहत बीपीएल और निम्न आय वर्ग परिवारों के लिए सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोग्राम लागू किया जाएगा, जो नेट-जीरो एलपीजी, बिजली और ईंधन खर्च पर केंद्रित होगा।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि प्रारंभिक चरण में यह परियोजना 6 माह के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू होगी। यदि यह सफल रहती है तो आगे इसका विस्तार किया जाएगा। योजना का लक्ष्य नागरिकों को पर्यावरण अनुकूल, आत्मनिर्भर और अफोर्टेबल हाउसिंग उपलब्ध कराना है। इसमें स्वच्छ ऊर्जा, हरित तकनीक और सतत विकास के मानकों को अपनाया जाएगा। नगर निगम और UNAccc का यह संयुक्त प्रयास नागरिकों के बिजली, एलपीजी और वाहन ईंधन पर होने वाले खर्च को कम करने पर केंद्रित होगा। एमओयू के तहत एक परिवार की औसत खर्च में 30% तक की बचत सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉ. श्रीकांत के. पाणिग्राही शामिल होंगे, जो जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ हैं। वे भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएँ दे चुके हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में जलवायु परिवर्तन सलाहकार, नीति आयोग की कार्ययोजना समिति के सदस्य सचिव तथा पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति के सदस्य हैं। साथ ही वे UNAccc के सह-अध्यक्ष, IISD (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट) के महानिदेशक, तथा कार्बन माइनस इंडिया (CMI) के निदेशक भी हैं। पर्यावरण संरक्षण, रणनीतिक योजना और कार्बन फाइनेंस में विशेष विशेषज्ञता रखने वाले डॉ. पाणिग्राही को कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी मौजूदगी इस ऐतिहासिक एमओयू को और अधिक महत्वपूर्ण बनाएगी।

श्री महाकाली भूतकाल के बंधनों से मुक्त कर आनंद प्रदान करती हैं

सहज योग संस्थापिका परम पूज्य आदिशक्ति श्री माताजी निर्मला देवी जी द्वारा वर्णित है कि, "हमारे अंदर तीन तरह की शक्तियां विराजती हैं। पहली जो शक्ति है मुख्यतः वह है इच्छा शक्ति। अगर परमात्मा की इच्छा ही नहीं होती तो वे संसार क्यों बनाते ? उनकी इच्छाशक्ति के अंदर से ही बाकी की शक्तियां निकली हैं। इसी इच्छाशक्ति को सहज योग की भाषा में महाकाली की शक्ति कहते हैं।" (नई दिल्ली 17 / 2/ 1989) महाकाली की शक्ति हमारे बायीं ओर ईड़ा नाड़ी से प्रवाहित होती है।परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी जी ने महाकाली का वर्णन करते हुए कहा है, "वे आनंद प्रदायिनी हैं और अपने भक्तों को आनंदित देखकर प्रसन्न होती हैं। आनंद ही उनका गुण और शक्ति है। विभिन्न चक्रों पर आप विभिन्न प्रकार के आनंद अनुभव करते हैं वह सब महाकाली की देन होती है।(फ्रांस 12/ 9 /1990)

अतः जब हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात विभिन्न सांसारिक बंधनों से बाहर निकलकर सहजयोग में सामूहिकता को आत्मसात करते हैं तो महाकाली तत्व हमारे अंतस में दृढ़ता से जागृत रहता है तथा हमें विभिन्न प्रकार के संकटों से रक्षित करता है।

श्री महाकाली दो तरह से कार्य करती हैं। जहां एक ओर हमें उनके प्रेममयी, आनंद एवं खुशी से परिपूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अति क्रूर क्रुद्ध और असुरों का वध करने वाले रौद्र रूप के। वे अपने दोनों ही स्वरुपों द्वारा अपनी पवित्र, सरल, विवेकी आत्मसाक्षात्कारी संतानों के हित के लिए कार्य करती हैं।

श्री माताजी ने अपनी अमृतवाणी में उपदेशित किया है कि," जब हम अपना आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करते हैं तो श्री महाकाली का प्रकटीकरण आरंभ हो जाता है। महाकाली में शुद्धिकरण की शक्ति है और वे स्वयं आप में पवित्र सती के रूप में रहती हैं। वही कुंडलिनी हैं, वही श्री महाकाली शक्ति हैं।" (फ्रांस 12/ 9/ 1990) स्त्रियों में श्री महाकाली शक्ति अपने शांत स्वरूप में शालीनता का गुण प्रकट करती हैं। श्री माताजी के अनुसार, "जब तक शालीनता स्त्री में कार्यान्वित नहीं होती तब तक गृहलक्ष्मी की शक्ति उसके अंदर प्रकटित नहीं होती।" (जयपुर 11/ 12 /1994) आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के पश्चात ध्यान धारणा द्वारा महाकाली की शक्ति जागृत की जा सकती है। जिससे हम बायीं ओर की समस्याओं, भूतकाल के बंधनों तथा अनेक प्रकार की मानसिक व शारीरिक बाधाओं से सहज में मुक्ति पा सकते हैं। सहज योग निशुल्क भी है और आसान भी सहजयोग ध्यान केंद्र की जानकारी हेतु टोल फ्री नंबर 1800 2700 800 पर संपर्क करें।

इंदौर ।कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध बिना हेलमेट के पेट्रोल देने पर खाद्य विभाग और तहसीलदार जूनी इंदौर ने खजराना काली माता मंदिर के पास स्थित M/s खजराना पेट्रो नीड्स नामक पेट्रोल पंप को सील किया

“संगीत जीवन में लय और ताल के संयोजन से भाव अभिव्यक्ति करने का श्रेष्ठ विकल्प है - डॉ. भरत शर्मा “

संस्था ‘सुरीली उड़ान’ और ‘स्वरम्’ का सफल मेघा शो ‘होंठों में ऐसी बात’

भारतीय चित्रपट के सफ़र से चुनिंदा और श्रेष्ठ गीतों की शृंखला का सफल मंचन इंदौर शहर के प्रतिष्ठित रवीन्द्र नाट्य गृह सभागार में आयोजित इस बेहतरीन कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ गायिका सरला मेंघानी द्वारा सरस्वती वंदना कर और मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। उक्त अवसर पर मुख्य अतिथि संस्कृति मंत्रालय सदस्य - डॉ भरत शर्मा ने कहा की संगीत अपनी लयबद्धतता से जीवन की खुशियों और दुखों के पल को अभिव्यक्त करते हैं। श्रृंगार रस की यह विधा भाव, लय, सुर और ताल का संयोजन कर हमें मुग्ध कर देती है। एकल और युगल गीतों का बेहतरीन प्रदर्शन कर मधु मुकेश, सरला मेंघानी, संजय छत्रकार, डॉ अल्पना आर्या, अश्मित सागर, रचना वैध, राकेश नागर, रिया श्रीवास्तव ने श्रीताओ को आल्हादित कर कार्यक्रम को सफल बना दिया। सभी सिंगर्स के रोमांटिक और रिदमिक सांग्स बहुत कठिन हाई पिच और लम्बी तान वाले संगीतबद्ध गानों पर सफल प्रस्तुति देकर श्रोताओं का मन मोह लिया। सिंफनी बैंड के पिंटू कसेरा और उनकी टीम द्वारा संगीत संयोजन बहुत ही कुशल और शानदार रहा। मुख्य अतिथि डॉ भरत शर्मा का स्वागत आयोजक श्री राम मेंघानी ने शाल व माला पहनाकर किया। विशेष अतिथियों श्री नामदेव कुकरेजा, श्री हरीश भाटिया, श्रीचंद शादीजा जी, श्री हरिओम कसेरा, श्री चंदू शिंदे जी और श्री सुदर्शन गुप्ता जी की उपस्थिति रही। संजय शर्मा ने कुशल मंच संचालन किया और लख्मीचंद वर्मा, कमल वीरवानी और जितेन्द्र गुप्ता ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम् भूमिका निभायी।

सादर... डॉ. भरत शर्मा, सदस्य - संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार

कर्तव्य निभाते हुए खाक़ी का मान बढ़ाने वाले पुलिसकर्मी को डीजीपी ने 50 हजार से अधिक राशि पुरस्कार से सम्मानित किया

चन्दन नगर थाना क्षेत्र मै मिले अज्ञात शव की गुत्थी सुलझी पुलिस टीम ने महज़ कुछ ही दिनों मै तीनों हत्यारों को गिरफ्तार किया चन्दन नगर थाना क्षेत्र मै शव मिलने पर आला-अधिकारियों ने निर्देश देते हुए टीमें गठित कि टीमों द्वारा लगातार हाथ लगें सबूतों को माध्यम बनाकर आसपास के कहीं सीसीटीवी कैमरे खंगाले जिसमें तीन संदिग्ध नज़र आएं टीम ने अपने विश्वसनीय मुखबिर से फुटेज की पहचान की तो फुटेज मै दिखाई देने वाले संदिग्ध आवेश उर्फ सुन्नी चिल्लर हुसैन, समीर उर्फ गुड्डा अब्बासी,सगीर के रूप हुईं पुलिस द्वारा पकड़ने पर तीनों ने लुटपाट करने के इरादे से हत्या करना कबूला वहीं आरोपियों के पास से मृतक का मोबाइल फोन, आधार कार्ड, लूटीं गई नकदी घटना मै प्रयुक्त चाकू और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई उक्त कारवाई की प्रशंसा करते हुए डीजीपी कैलाश मकवाना ने जांच दल के अधिकारीयों जवानों को अलग अलग नगद राशि पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

सम्मानित पुरस्कार लेने वाले अधिकारी जवान रहें

एस आईं सौरभ कुशवाहा, 8000 रूपए
एस आई रामकुमार रघुवंशी,7000
प्रधान आरक्षक बलराम चौहान,7000
आरक्षक जोगेश लश्करी,6000
धीरज पांडेय,6000
विश्वेंद्र जाट,6000
कृष्ण चंद्र शर्मा,4000
गौरव परमार,3000
राकेश विश्वकर्मा,3000

ट्रेडमार्क ब्लैंडर्स प्राइड V/s. लंदन प्राइड सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रीमियम व्हिस्की खरीदने वाले साधारणतः शिक्षित होते है, इसलिए कन्फ्यूजन की संभावना कम

नई दिल्ली। ‘ब्लेंडर्स प्राइड’ इंपीरियल ब्लू व्हिस्की और सीग्राम के ब्रांड वाली कंपनी पेर्नोड रिकार्ड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इंदौर के करणवीर सिंह छाबड़ा के स्वामित्व वाली ‘जेके एंटरप्राइजेज’ के व्हिस्की ब्रांड ‘लंदन प्राइड’ के खिलाफ दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन और पासिंग ऑफ (Passing-off) मामले में पेर्नोड रिकार्ड कंपनी को कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के 3 नवंबर, 2023 के आदेश को बरकरार रखा।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जब पेर्नोड रिकार्ड का पंजीकरण केवल ‘ब्लेंडर्स प्राइड नामक समग्र ट्रेडमार्क के लिए है, तो वह ‘प्राइड’ शब्द पर कोई विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकती। मामले में “लंदन प्राइड की तरफ से सीनियर एड. श्याम दीवान और अभिमन्यु भंडारी के साथ वैभव मिश्रा, एकांश मिश्रा, आयुष जैन, रोंगन चौधरी और शुभम तिवारी ने की। जबकि ब्लेंडर्स प्राइड की ओर से देश के नामचीन सीनियर एडव्होकेट मुकुल रोहतगी और नीरज किशन कौल के साथ डेढ दर्जन वकीलों की टीम ने पैरवी की थी।

क्या था मामला?

पेर्नोड रिकार्ड ने आरोप लगाया था कि ‘लंदन प्राइड’ ब्रांड उसके पंजीकृत ट्रेडमार्क और ‘ट्रेड ड्रेस (पैकेजिंग और डिजाइन) से काफी मिलता-जुलता है। कंपनी ने दावा किया कि ‘लंदन प्राइड’ की पैकेजिंग, कलर स्कीम, लेबल और ‘प्राइड’ शब्द का प्रमुख इस्तेमाल उपभोक्ताओं में भ्रम पैदा कर सकता है। कंपनी ने अदालत से ‘लंदन प्राइड’ के इस्तेमाल पर स्थायी रोक लगाने, उल्लंघनकारी सामग्री को नष्ट करने और मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपये की मांग की थी।

कमल यादव को राजधानी दिल्ली में मिला सामाजिक सेवा रत्न पुरस्कार

संजय प्रेम जोशी

बागली। नगर पालिका महासंघ परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एवं बागली नगर परिषद अध्यक्ष प्रति निधि कमल यादव कोदिल्ली के मीडिया मंच पर सामाजिक सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया इस अवसर पर मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक जोशी उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला बाजीराव पेशवा के वंशज प्रमोद पेशवा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तपन भोमीक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल देवास विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष राजेश यादव सहित कई प्रबुद्ध हस्तियां उपस्थिति रही सामाजिक सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित कमल यादव ने बताया कि भारत की राजधानी दिल्ली में सम्मानजनक मंच पर उनका सम्मान

होना बागली का सम्मान है। इसी प्रवास के दौरान उन्होंने खंडवा संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। मंच पर उपस्थित दीपक जोशी तपन भौमिक एवं राजेश व्यास ने यादव को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बागली नगर परिषद मे करोड़ों रुपए के विकास कार्य होकर पूरा बागली नगर लगातार विकास कर रहा है। श्री यादव के सम्मानित होने पर उनके इष्ट मित्रों ने उन्हें बधाई देते हुए खुशी जाहिर की।

नकली कीटनाशक के संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्राप्त हुई कई शिकायतें

क्लोरिमयूरॉन एथिल नामक हर्बिसाइड खरपतवार नाशक के उपयोग से खराब हुई सोयाबीन की फसलें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के निर्देशों पर कृषि विभाग ने की तत्काल कार्रवाई बाजार से खरपतवार नाशक के सैम्पल जब्त कर की गई जांच जांच में हर्बिसाइड के नमूने घटिया पाए गए मध्य प्रदेश के 3 जिलों विदिशा, देवास और धार में डिफॉल्टर कंपनियों के खिलाफ दर्ज की गई FIR जिन क्षेत्रों में खराब हर्बिसाइड की बिक्री हुई है, वहाँ डीलरों के लाइसेंस निलंबित किए गए राज्य सरकारों को भी जब्त हर्बिसाइड के नतीजे आने तक लाइसेंस निलंबित करने के निर्देश कंपनियों के बचे हुए स्टॉक की बिक्री पर भी लगाई गई रोक फसलों को नुकसान से बचाने के लिए क्लोरिमयूरॉन एथिल खरपतवार नाशक का उपयोग न करने की दी सलाह।

आयकर अधिकारियों का दो दिवसीय अधिवेशन कल से इंदौर में

आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ की/का 48वाँ द्विवार्षिक आमसभा/ अधिवेशन 21/08/2025 एवं 22/08/2025 को इंदौर के प्राइड होटल में किया जा रहा है। आयकर विभाग मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्र के 400 से अधिक राजपत्रित अधिकारी इसमें भाग लेने के लिए इंदौर में पहुंच चुके है। ITGOA अर्थात इनकम टैक्स गैजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन की नींव सन् 1933 में रखी गई थी। प्रत्येक दो वर्ष में ITGOA की आमसभा कराई जाती है जिसमें आयकर विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा एवं मंथन किया जाता है एवं साथ ही साथ आयकर राजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन के विभिन्न राजनीतिक पदों के लिए चुनाव भी संपन्न कराए जाते हैं। 21 तारीख को एसोसिएशन की चर्चा एवं मंथन के उपरांत शाम को प्रत्याशियों का नामांकन एवं 22 तारीख ITGOA के चुनाव होगे एवं इस दौरान सांस्कृतिक आयोजन एवं अधिकारियों के मिलन समारोह के साथ ही अन्य आयोजन भी किए जाएंगे।22 तारीख की शाम को आयकर राजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन के चुनावों के नतीजे घोषित होंगे और इस दौरान ITGOA के शीर्ष नेतृत्व अधिकारी एवं आयकर विभाग के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

डेमोग्राफी मिशन से राष्ट्रीय सुरक्षा को मिलेगा नया आधार

डेमोग्राफी मिशन के पक्ष विपक्ष में अंतहिन विवाद किया जा सकता है पर दो टके का सवाल यही है कि देश को किसी भी हालत में आंतरिक व राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिये। जिस तरह से देश के कई पॉकेट्स में तेजी से डेमोग्राफिक असंतुलन बन रहा है उसे देखते हुए देरी से ही सही पर डेमोग्राफिक मिशन की घोषणा स्वागतीय है। सभी को दलीय राजनीति से उपर उठकर इसका स्वागत किया जाना चाहिए। यह साफ हो जाना चाहिए कि देश की आंतरिक और सीमावर्ती सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। कोई भी राष्ट्र इसे स्वीकार भी नहीं करेगा। घुसपैठियों के कारण जिस तरह की समस्याएं और आदिवासियों की भूमि पर कब्जा करने से लेकर देश की आम जनता के लिए लोक हितकारी योजनाओं में सैंध लगा रहे हैं उसे रोका जाना अतिआवश्यक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस भावना के साथ मिशन की घोषणा की है उसी भावना और मंशा के साथ इस मिशन को आकार दिया जाना चाहिए।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए हाईपॉवर डेमोग्राफी मिशन की घोषणा कर देश के सीमावर्ती जिलों में अवैध घुसपैठियों और अन्य कारणों से देश में आ रहे डेमोग्राफी बदलाव की समस्या के समाधान की आस बंधी है। देश के कुछ हिस्सों खासतौर से सीमावर्ती जिलों में आबादी असंतुलन से बड़ी समस्या होती जा रही है। डेमोग्राफी मिशन को राजनीतिक लाभ हानि की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। अपितु जो तस्वीर देश में सामने आ रही है उससे सबसे बड़ी और गंभीर समस्या सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर आ गई है। हांलाकि राजनीतिक दल वोट बैंक के चलते बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं सहित अवैध प्रवास कर रहे लोगों के पक्ष में आ जाते हैं पर यह सीधा-सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर मुद्दा होता जा रहा है। पिछले दिनों अमेरिका के लॉस एंजिल्स की घटना पर ध्यान दिया जाना जरुरी हैं जहां वाहनों को जलाते और लूटपाट मचाकर कानून व्यवस्था को ही तहस-नहस करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। फ्रांस में भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। रवांडा, पश्चिमी वाल्मिक, यारोपीय देश आदि दुनिया के अनेक देश इस समस्या से दो चार होते रहे हैं। अमेरिका के चुनाव परिणाम किस तरह से लांस एंजिल्स में प्रभावित होते हैं वह सबके सामने हैं। हमारे देश में पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, झारखण्ड आदि कई दृष्टि से प्रभावित हो रहे हैं। बांग्लादेशी, रोहिंग्या अवैध घुसपैठ कर देश के हर कोने में आसानी से पहुंच रहे हैं और जब किसी तरह की घटना होती हैं तो इनके द्वारा आंतक और अशांति फैलाई जाती है वह भी किसी से नहीं है।

दुनिया के देशों में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाती है। चीन जैसे देश तो इतने कठोर कदम उठाते हैं कि कभी पता ही नहीं चल सकता की स्वतंत्रता क्या होती है उसका पता ही नहीं चलता। अफगान सीमा पर तो गोली मार दी जाती है। क्यूबा में राजनीतिक जेल में बंद हो जाते हैं। सउदी अरब में भी जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक इसके विपरीत हमारे हालात है। हमारे यहां राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है। सोशल एक्टिविस्ट सक्रिय हो जाते हैं। हमारे यहां तो अवैध कब्जा, राशनकार्ड, निःशुल्क सुविधाओं से लाभान्वित करवाने वाले सक्रिय हो जाते हैं। सच में देखा जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा से एक तरह से लेना देना ही नहीं रहता। यही कारण है कि बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो या पाकिस्तान परस्त लोग देश की सुरक्षा और अशांति फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। ज्योंही कहीं पर कोई कार्रवाई करने को प्रशासन आगे आता है तो इनके बचाव में मानवीयता का नारा उछालने लगते हैं। यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण हालात है।

डेमोग्राफी का सबसे पहले प्रयोग 1855 में बेल्जियम के अकिल गुडलार्ड ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन डेमोग्राफी में किया। हांलाकि जनसांख्यकी की बात राबर्ट माल्थस 1766 से 1834 में कर चुके हैं और उन्होंने पूरी थ्योरी प्रस्तुत की है। डेमोग्राफिक अध्ययन को दो तरह से समझना पड़ेगा। एक तो सामान्य तौर पर जिस तरह से आयु-धर्म के आधार पर जनसांख्ययीय अध्ययन कर विकास की रुपरेखा तैयार की जाती है। यह एक तरह से इस समस्या का समाधान डेमोग्राफिक अध्ययन के परिणामों के आधार पर नीति व योजनाएं बनाकर की जाती है और की जा सकती है। इसके ठीक विपरीत जिस तरह से देश में अराजकता और अशांति फैलाने और घुसपैठ व वर्गविशेष के कारण जनसंख्या में बदलाव लाकर क्षेत्रीय असंतुलन पैदा करने का प्रयास किया जाता है वह अधिक गंभीर व चिंतनीय हो जाती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा डेमोग्राफी मिशन की घोषणा के निश्चित रुप से राजनीतिक अर्थ निकालने के प्रयास किये जायेंगे। इसे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक द्वारा घुसपैट और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध मदरसों आदि द्वारा संचालित गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है उससे जोड़कर देखने का प्रयास किया जाएगा। यहां इसको भी ध्यान में रखना होगा कि अवैध घुसपैठियों द्वारा सीमावर्ती जिलों में जिस तरह से आदिवासियों की जमीन और संपत्ती पर कब्जा किया जा रहा है यह भी किसी से छिपा नहीं हैं। बीएसएफ और एसएसएफ द्वारा जिस तरह से सरकार को लगातार रिपोर्टें दी जाती रही हैं पहलीवार उसे गंभीरता से लिया जा रहा है। बीएसएफ के पूर्व एडीजी पीके मिश्रा का कहना है कि डेमोग्राफी मिशन को राजनीतिक चश्में से नहीं देखा जाना चाहिए। यह तो सीधा सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। आज समूचा देश डेमोग्राफिक समस्या से दो चार हो रहा है। इसे नेपाल, बांग्लादेश, सीमावर्ती इलाकों में मुसलमान और हिंदुओं की आबादी में आ रहे बदलाव आदि से देखना होगा। प्रधानमंत्री की चिंता किसी एक क्षेत्र या सीमा तक नहीं है। इसका बड़ा कारण देश में डेमोग्राफिक समस्या की गंभीरता को समझने से ही होगा। आने वाले दिनों में बिहार, बंगाल आदि में चुनाव होने हैं और राजनीतिक दल इस घोषणा को निश्चित रुप से मुद्दा बनायेंगे, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। पर धरातलीय समस्या से आंख नहीं मूंदी जा सकती। बंगाल की मुर्शिदाबाद, बिहार का किशनगंज, उत्तरप्रदेश का नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र, असम के आदिवासी क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल और झारखण्ड के हालात सामने हैं। सीमावर्ती सहित इन क्षेत्रों में मदरसों द्वारा जिस तरह का वातावरण तैयार किया जा रहा है उससे डेमोग्राफी बदलती जा रही है। कश्मीर का उदाहरण हमारे सामने है आज कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से विस्थापन हो चुका है।

डेमोग्राफी मिशन के पक्ष विपक्ष में अंतहिन विवाद किया जा सकता है पर दो टके का सवाल यही है कि देश को किसी भी हालत में आंतरिक व राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिये। जिस तरह से देश के कई पॉकेट्स में तेजी से डेमोग्राफिक असंतुलन बन रहा है उसे देखते हुए देरी से ही सही पर डेमोग्राफिक मिशन की घोषणा स्वागतीय है। सभी को दलीय राजनीति से उपर उठकर इसका स्वागत किया जाना चाहिए। यह साफ हो जाना चाहिए कि देश की आंतरिक और सीमावर्ती सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। कोई भी राष्ट्र इसे स्वीकार भी नहीं करेगा। घुसपैठियों के कारण जिस तरह की समस्याएं और आदिवासियों की भूमि पर कब्जा करने से लेकर देश की आम जनता के लिए लोक हितकारी योजनाओं में सैंध लगा रहे हैं उसे रोका जाना अतिआवश्यक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस भावना के साथ मिशन की घोषणा की है उसी भावना और मंशा के साथ इस मिशन को आकार दिया जाना चाहिए और पूरी कार्ययोजना बनाकर इसे जल्द से जल्द से आकार दिया जाना चाहिए ताकि डेमोग्राफिक मिशन अपना कार्य आरंभ कर सके। डेमोग्राफिक संतुलन व सीमाओं की सुरक्षा के साथ ही योजनावद्ध तरीके से असंतुलन के जो प्रयास किये जा रहे हैं उस पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना जरुरी है। इसे राजनीतिक विवाद से दूर ही रखा जाना चाहिए। सोशल एक्टिविस्टों को भी राष्ट्रहित को पहली प्राथमिकता देनी ही होगी।

मेडिकल जांच के नाम पर बड़ा घोटाला, कांग्रेस का आरोप

300 करोड़ की गड़बड़ी से स्वास्थ्य व्यवस्था पर संकट

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य के जिला अस्पतालों में मेडिकल जांच के नाम पर 300 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के 85 अस्पतालों में निजी कंपनियों द्वारा जांचें की जा रही हैं और इन कंपनियों ने मरीजों से वसूल की जाने वाली राशि सामान्य दर से 25 प्रतिशत अधिक रखी है। कांग्रेस ने दावा किया है कि यह सारा खेल स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ खिलवाड़ करने और चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने टेंडर से जुड़े दस्तावेज भी मीडिया के सामने रखे। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग ने साल 2019 में जिला अस्पतालों में 70 से अधिक तरह की मेडिकल जांच का जिम्मा दो निजी कंपनियों ङ्क साइंस हाउस और पीओसीटी सर्विसेज ङ्क को सौंपा था। ये कंपनियां पांच साल से लगातार अस्पतालों में जांच का कार्य कर रही हैं। आरोप यह है कि इन कंपनियों ने एनएबीएल (नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज) की दरों के आधार पर भुगतान लिया, जबकि सरकारी अस्पतालों की प्रयोगशालाओं के पास एनएबीएल सर्टिफिकेट मौजूद ही नहीं था। इस तरह गैर-एनएबीएल लैब के बावजूद मरीजों से 25 फीसदी अधिक शुल्क वसूला गया। कांग्रेस का कहना है कि इन कंपनियों ने अब तक लगभग 800 करोड़ रुपए का बिल लगाया है, जिसमें 25 प्रतिशत की अतिरिक्त वसूली जोड़ने पर करीब 300 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आता है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार ने हाल ही में इस ठेके को और आगे बढ़ा दिया है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में इसी तरह की सेवाएं कहीं कम दरों पर उपलब्ध हैं। कांग्रेस ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा है कि स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवा में इस तरह का भ्रष्टाचार जनता के जीवन से खिलवाड़ करने जैसा है।

सरकारी स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण कार्य उच्च गुणवत्तापूर्ण हो

भोपाल (नप्र)। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 में पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा मुद्रित की जाने वाली किताबें उच्च गुणवत्ता की हों। उन्होंने कहा कि मुद्रण कार्य से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं तय समय-सीमा में पूरी की जायें। उन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तकों का वितरण शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही पूरा किया जाये। यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह बुधवार को मंत्रालय में पाठ्य पुस्तक निगम की गवर्निंग बॉडी की बैठक ली। बैठक में सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. संजय गोयल, आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता, वित्त, माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

बैठक में पाठ्य पुस्तक निगम के एमडी श्री विनय निगम ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में करीब 9 करोड़ पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण होगा। इसके लिये ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत निविदा की प्रक्रिया होगी। निगम शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 10 मार्च 2026 तक सभी पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण कार्य पूरा कर लेगा। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष अप्रैल 2025 में शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण शुरू किया गया था। इस वर्ष अब तक लगभग सभी पाठ्य पुस्तकों का वितरण विद्यार्थियों को किया जा चुका है। बैठक में बताया गया कि निगम ने कुछ सरकारी स्कूलों को खेल-कूद मैदान, अतिरिक्त कक्ष और नवीन कक्ष निर्माण के लिये अनुदान राशि मंजूर की है।

किताबों की पांडुलिपि डेढ़ माह में मिलेगी

बैठक में भी बताया गया कि राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा अगले शैक्षणिक सत्र के लिये एनसीईआरटी और एससीईआरटी से किताबों की पांडुलिपि सितंबर 2025 अंत तक पाठ्य पुस्तक निगम को उपलब्ध करा दी जायेंगी। मध्यप्रदेश, देश के उन चुनिंदा राज्यों में है, जहां बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सत्र शुरू होते ही वितरित की गयीं।

स्थानीय भाषा में सामग्री विकास

स्कूल शिक्षा विभाग ने 8 स्थानीय भाषाओं- बुन्देली, बघेली, मालवी, निवाड़ी, गोंडी, भीली, बारेली और कोरकू भाषाओं में सामग्री का विकास किया है। विभाग का यह प्रयास बच्चों में स्थानीय भाषा के प्रति लगाव के उद्देश्य से किया गया है।

भ्रष्टाचार की नींव पर बना बिजली विभाग का दफ्तर बना मौत का जाल, कर्मचारी हेलमेट पहनकर कर रहे काम

मध्य प्रदेश। जहां एक ओर सरकार नए इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक विकास के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर हकीकत इससे बिल्कुल उलट तस्वीर पेश करती है। रीवा जिले का बिजली विभाग कार्यालय इस विरोधाभास का जिंदा सबूत बन चुका है। नेहरू नगर स्थित इस कार्यालय की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहां काम करने वाले कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने को मजबूर हैं। आलम यह है कि दफ्तर में कंप्यूटर ऑपरेटर तक को अब अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि कभी भी ऊपर से प्लास्टर टूटकर गिर सकता है। कुछ दिन पहले ही एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब अचानक छत का प्लास्टर भरभराकर गिरा और वहां काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर आश्रित मिश्रा के पैर पर आ गिरा। गनीमत रही कि उनका सिर बच गया, वरना गंभीर चोट लग सकती थी। इसके बाद से कर्मचारियों ने खुद ही एहतियात के तौर पर हेलमेट लगाकर काम करना शुरू कर दिया। कर्मचारी बताते हैं कि कई बार विभागीय अधिकारियों को इस खतरनाक स्थिति से अवगत कराया गया, लेकिन न तो मरम्मत हुई और न ही भवन की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया। हैरानी की बात यह है कि यह भवन सिर्फ 6 साल पहले ही बना था और आज इसकी हालत खंडहर जैसी हो चुकी है। कर्मचारियों का कहना है कि घटिया क्वालिटी के निर्माण और भ्रष्टाचार की वजह से यह स्थिति बनी है। लगातार प्लास्टर और छत गिरने की घटनाएं कर्मचारियों की जान पर भारी पड़ रही हैं। दफ्तर में हर दिन काम करने से पहले यह डर बना रहता है कि अगली बार गिरने वाला प्लास्टर कहीं किसी की जिंदगी पर न भारी पड़ जाए। रीवा बिजली विभाग के जे.ई. अनिल सिंह ने भी इस समस्या को स्वीकार करते हुए कहा कि बीते चार सालों से वरिष्ठ अधिकारियों को बार-बार शिकायत की जा रही है, लेकिन हर बार केवल निरीक्षण कर फंड की कमी का हवाला देकर मामले को टाल दिया जाता है। स्थिति अब इतनी भयावह हो चुकी है कि कर्मचारी वॉशरूम जाने से भी डरते हैं। उनका कहना है कि वॉशरूम का गेट तक टूटा हुआ है और छत गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। मजबूरी में बहुत ही इमरजेंसी में ही वहां जाना पड़ता है। दरअसल, यह पूरा मामला साफ करता है कि किस तरह भ्रष्टाचार की नींव पर तैयार सरकारी इमारतें कुछ ही सालों में खंडहर बन जाती हैं और जिनके सहारे काम करने वाले कर्मचारी हर दिन मौत के साए में जीने को मजबूर होते हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक सरकार और विभाग आंखें मूंदे रहेंगे और कर्मचारियों की सुरक्षा को इस तरह से दांव पर लगाया जाता रहेगा।

एनएसयूआई का भोपाल ड्रग्स फैक्ट्री मामले पर अनोखा प्रदर्शन, सरकार को कुंभकरण की नींद से जगाने का प्रयास

भोपाल। राजधानी भोपाल में उजागर हुई अवैध ड्रग्स फैक्ट्री ने पूरे प्रदेश को चौंका दिया है। डीआरआई की कार्रवाई में करोड़ों रुपए की मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स और भारी मात्रा में कच्चा माल बरामद हुआ। इस मामले में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने आरोप लगाया की घटना साफ प्रदेश सरकार की आँखों के सामने नशे का व्यापार फलता-फूलता रहा और शासन कुंभकरण की नींद सोता रहा। इसी मामले को लेकर बुधवार को एनएसयूआई ने अनोखा प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने ढोल ताशे और सीटियों के माध्यम से सरकार को उसकी गहरी नींद से जगाने का प्रयास किया।

एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य सोनी ने कहा की जिस प्रकार से न जाने कितने समय से राजधानी भोपाल में उक्त अवैध फैक्ट्री नशे का व्यापार कर युवाओं एवं छात्रों के बिच इस जहर को घोलने का कार्य कर रही थी, डीआरआई ने न सिर्फ वहां से करीब 92 करोड़ की ड्रग्स बरामद करी है बल्कि 595 किलो कच्चा माल भी जब्त किया है । यह सिर्फ एक ड्रग्स फैक्ट्री का मामला नहीं, इस तरह के और भी कई मामले जैसे गत वर्ष अक्टूबर महीने में गुजरात से आई 1800 करोड़ की ड्रग एनसीबी ने भोपाल से बरामद करी थी, जिसके अलावा तस्करों के बड़े रैकेट का खुलसा भी भोपाल से ही हुआ है । सोनी ने कहा की राजधानी भोपाल नशे की राजधानी बनने की ओर अग्रसर है और प्रदेश सरकार कुंभकरण की नींद सो रही है। भोपाल एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने कहा की यह प्रदर्शन मध्यप्रदेश शासन को चेतावनी है कि यदि नशे के कारोबारियों और उन्हें संरक्षण देने वालों पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई, तो एनएसयूआई सड़कों पर और भी बड़े आंदोलन करेगी। इस दौरान एनएसयूआईप्रदेश उपाध्यक्ष विदुषी शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष रवी परमार, जिला महासचिव तारिक खान, जिला महासचिव रेहान अहमद , एकांत गुर्जर,मुकुल परासर, वरुण निमोड़ा, संस्कार प्रजापती, हर्ष पाठक, अजय उईके, प्रवीण, उमंग रघुवंशी, अभिषेक जाटव,आकांक्षा मिश्रा, मानसी प्रधान, युवराज वर्मा, राजा रघुवंशी एवं अन्य साथी शामिल रहे।

40 साल से ज्यादा पुराना मकान पिलर धंसने के कारण भरभरा कर गिरा, खाली होने से कोई जनहानि नहीं

इंदौर। इंदौर के तोड़ा क्षेत्र में एक खतरनाक मकान भरभरा कर गिर पड़ा जिस वक्त यह हादसा हुआ, तब न तो मकान के भीतर कोई था और न ही आसपास लोग खड़े थे। इस कारण कोई जनहानि नहीं हुई। समीप के खाली प्लॉट पर खुदाई की जा रही थी। इस कारण पास का मकान गिर पड़ा। तीन साल पहले जवाहर मार्ग से चंद्रभागा जूनी इंदौर की रिवर साइड रोड बनाने के लिए 50 से ज्यादा मकानों के आगे के हिस्से हटाए गए थे, लेकिन बचे हिस्से रहने लायक नहीं बचे थे। पिछले दिनों नगर निगम ने 18 आधे मकानों को भी तोड़ा था,ताकि हादसा न हो।

बुधवार दोपहर मकान गिरने की घटना के बाद आसपास के लोग डर गए। उन्हें आशंका थी कि कही मलबे में कोई दबा न हो। मौके पर रावजी बाजार पुलिस भी पहुंची और जांच की। मलबे में किसी के दबे होने की सूचना नहीं मिली। यह मकान सैय्याद अखलाक का है। इसका कुछ हिस्सा सड़क की चौड़ाई की जद में आने के कारण तोड़ा गया था, लेकिन मकान मालिक ने बचे हिस्से की मरम्मत नहीं की थी। मकान

खतरनाक स्थिति में होने के कारण चार माह पहले परिवार के लोगों मकान खाली कर दूसरी जगह रहने चले गए थे।

पिलर धंसने के कारण गिरा मकान

तीन मंजिला मकान पिलर धंसने के कारण गिरा। यह मकान 40 साल से ज्यादा पुराना था और वर्षों तक कई किराएदार भी रहते थे। इस नए मार्ग पर कुछ अन्य मकान भी है, जो अधूरे टूटे हुए है। अब नगर निगम की टीम उन मकानों की पड़ताल भी कर रही है। नगर निगम का अमला झांकी मार्ग के खतरनाक मकानों की भी जांच कर उन्हें नोटिस देगा, ताकि चल समारोह के दौरान हादसा न हो।

इंदौर का राजा रघुवंशी हत्याकांड

जन्मदिन पर फिर इंदौर पहुंची शिलांग पुलिस, जेल में भी मुस्कुराती रही आरोपी सोनम

इंदौर। चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच में जुटी शिलांग पुलिस एक बार फिर इंदौर पहुंची है। खास बात यह है कि पुलिस की यह कार्रवाई उस दिन हुई जब हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और उसका भाई गोविंद, का जन्मदिन है । राजा रघुवंशी की हत्या के बाद से ही सोनम जेल में है, लेकिन चर्चाओं में यह बात सामने आ रही है कि जेल के अंदर भी उसकी मुस्कुराहट और बेपरवाही बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक, शिलांग पुलिस हत्या में इस्तेमाल मोबाइल फोन की डिटेल खंगाल रही है। जांच में पता चला कि हनीमून पर शिलांग जाने से पहले सोनम ने दो नए मोबाइल फोन खरीदे थे। इन्हीं फोनों के जरिए सोनम और उसके प्रेमी राज ने राजा की हत्या की साजिश रची थी। दिलचस्प बात यह भी है कि पिछले साल सोनम के जन्मदिन पर बड़े स्तर पर सेलिब्रेशन हुआ था, लेकिन इस बार उसका जन्मदिन सलाखों के पीछे बीत रहा है। वहीं, उसके पति की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए शिलांग पुलिस इंदौर में लगातार पड़ताल कर रही है। इंदौर के पुलिस अधिकारियों ने जब शिलांग पुलिस से नॉर्मल चर्चा में पूछा कि क्या अपराधियों के व्यवहार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आया तो शिलांग पुलिस की टीम ने बताया जेल के अंदर भी सोनम रघुवंशी की मुस्कुराहट बरकरार है और किसी को भी हत्या करने के बाद पछतावा नहीं है।

इंदौर की दो सीटों पर भी वोट चोरी का असर, कांग्रेस ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

इंदौर। मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पिछले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में 27 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी वोट चोरी की वजह से मामूली अंतर से हार गए। इन सीटों में इंदौर की दो सीटें भी शामिल हैं। सिंघार ने कहा कि चुनाव से पहले मतदाता सूची में संदिग्ध ढंग से लाखों नाम जोड़े गए और इससे भाजपा को प्रत्यक्ष लाभ मिला। भोपाल में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि जनवरी से अगस्त 2023 तक सात महीने में प्रदेश की मतदाता सूची में करीब 4 लाख नाम जुड़े, जबकि इसके बाद सिर्फ दो महीने यानी अगस्त से अक्टूबर तक अचानक 16 लाख नए नाम जुड़ गए। इस पर और संदेह इसलिए बढ़ गया क्योंकि 9 जून 2023 को चुनाव आयोग ने पांच राज्यों की मतदाता सूची से जुड़ी जानकारियों को वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं करने और किसी भी तरह से साझा न करने के निर्देश दिए थे। सिंघार ने यह भी खुलासा किया कि 22 दिसंबर 2022 को राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों को 8.51 लाख नकली और डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने का निर्देश दिया था। लेकिन किस जिले से कितनी प्रविष्टियां हटाई गईं, इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। उनका कहना है कि 27 विधानसभा क्षेत्रों में अचानक बड़ी संख्या में मतदाता जोड़ने का फायदा भाजपा को हुआ और कांग्रेस के प्रत्याशी मामूली अंतर से हार गए। इंदौर जिले का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि देपालपुर विधानसभा में 2 अगस्त 2023 तक मतदाताओं की संख्या 2 लाख 53 हजार 412 थी, जबकि 4 अक्टूबर तक यह बढ़कर 2 लाख 67 हजार 360 हो गई। यानी केवल दो महीने में 13 हजार 948 मतदाता जुड़े। संयोग यह रहा कि यहां कांग्रेस प्रत्याशी 13 हजार 698 मतों से पराजित हुआ।इसी तरह इंदौर विधानसभा-5 में मतदाताओं की संख्या 2 अगस्त को 3 लाख 89 हजार 928 थी, जो 4 अक्टूबर तक बढ़कर 4 लाख 13 हजार 447 हो गई। यानी इस क्षेत्र में 23 हजार 519 मतदाता बढ़े। नतीजतन, कांग्रेस का उम्मीदवार यहां 15 हजार 671 मतों से हार गया। सिंघार ने आरोप लगाया कि यह सब योजनाबद्ध तरीके से किया गया, ताकि भाजपा को सीटों पर अनैतिक लाभ मिल सके। उन्होंने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले की जांच कराने और मतदाता सूची में हुए संशोधनों की पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की।

जल संकट से निपटने की पहल, नगर निगम ने लगाए 200 रिचार्ज शाफ्ट, बारिश का पानी अब पहुंचेगा जमीन तक

इंदौर। बारिश के पानी को बर्बाद होने से बचाने और भूजल स्तर को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने शहरभर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभियान को तेज़ी से आगे बढ़ाया है। इस अभियान के तहत निगम ने प्रमुख स्थानों पर रिचार्ज शाफ्ट तैयार कर पानी को जमीन तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। एक शाफ्ट बनाने में सवा से डेढ़ लाख रुपये का खर्च आता है और अब तक निगम 200 से अधिक शाफ्ट बनवा चुका है। निगम ने पिछले कुछ वर्षों से शहर के प्रमुख क्षेत्रों और कॉलोनियों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की योजना पर काम शुरू किया था। रहवासी संघों की मदद से कालोनियों में इस व्यवस्था को लागू करने के साथ ही अधिकृत प्लंबर तैनात किए गए, जिनकी दरें भी तय कर दी गईं। इस कदम से बड़ी संख्या में कॉलोनियों ने भी पानी बचाने की दिशा में कदम बढ़ाए। अधिकारियों का कहना है कि इस बार निगम ने 300 स्थानों पर रिचार्ज शाफ्ट लगाने का लक्ष्य तय किया था, जिनमें से 200 का काम पूरा हो चुका है। बाकी 100 स्थानों पर भी आने वाले दिनों में यह कार्य किया जाएगा। नगर निगम को इस काम में बड़ी कंपनियों और बैंकों का सहयोग मिला है। उनके सीएसआर फंड के जरिए इन रिचार्ज शाफ्टों का निर्माण कराया गया, जिससे निगम को सीधे तौर पर ढाई करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई। पहले भी निगम ने इसी पैटर्न पर शहर के छह बड़े तालाबों को संवारा और उनके आसपास सौंदर्यीकरण कार्य करवाए, जिससे शहर का स्वरूप बदला और जल संरक्षण की दिशा में अहम योगदान मिला।

बारिश ने फिर बढ़ाई मुसीबत, सिंगापुर टाउनशिप अंडरपास में पानी भरने से रास्ता बंद, बच्चों और राहगीरों को भारी दिक्कत

इंदौर। शहर में कल से लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर सिंगापुर टाउनशिप अंडरपास की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। मंगलवार सुबह अंडरपास में पानी भर जाने से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। हालात यह रहे कि न सिर्फ वाहनों की आवाजाही रुकी बल्कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। बारिश के मौसम में हर बार यही समस्या सामने आती है, मगर सालों से इसका स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि मांगलिया के पास नया पुल तो बनाया जा रहा है, लेकिन अंडरपास की समस्या को लेकर न तो रेलवे गंभीर है और न ही स्थानीय प्रशासन ने कोई ठोस कदम उठाया है। लगातार पानी भरने से अंडरपास की सड़कों की हालत भी बेहद खराब हो गई है। कीचड़ और गड्ढों के कारण वाहन फंसने का खतरा बना रहता है। सुबह जब लोग काम पर निकल रहे थे तो उन्हें अंडरपास में पानी भरने की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूल जाने वाले बच्चों और उनके पालकों को हुई। स्कूल बस ड्राइवरों ने मजबूरी में बसें अंडरपास के दूसरी तरफ रोक दीं। इसके बाद बच्चों के अभिभावकों को रेलवे क्रॉसिंग के इस पार अपने वाहन खड़े कर बच्चों को पैदल ले जाना पड़ा। स्थानीय निवासी राजेश तंवर ने बताया कि अंडरपास की सड़क की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है।

तीन नई टीपीएस योजनाओं पर भी लगी रोक, आवासीय और वाणिज्यिक विकास पर असमंजस गहराया

इंदौर। शहर में विकास को गति देने के लिए बनाई जा रही नई टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस) भी अब रुकावटों में फंस गई हैं। प्राधिकरण ने जहां पहले से ही अहिल्या पथ से जुड़ी आधा दर्जन योजनाओं के अभिन्यास मंजूर करने पर रोक लगा रखी है, वहीं हाल ही में हुई बोर्ड बैठक में तीन और नई योजनाओं पर भी यही रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। नगर तथा ग्राम निवेश को भेजे गए पत्र में साफ निर्देश दिए गए हैं कि टीपीएस-11, 12 और 13 में शामिल जमीनों पर किसी भी प्रकार की अभिन्यास मंजूरी नहीं दी जाए। ये तीनों नई योजनाएं धार और खंडवा रोड पर प्रस्तावित की गई हैं, जिनका उद्देश्य केवल आवासीय विकास ही नहीं बल्कि वाणिज्यिक मंडी, थोक बाजार और मास्टर प्लान की नई सड़कों का निर्माण भी है। नावदापंथ, निहालपुरमुंडी और कनाडिया क्षेत्र में इन योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बोर्ड संकल्प के आधार पर प्रस्ताव शासन को भेज दिए गए हैं। प्राधिकरण ने पिछले साल ही अहिल्या पथ के लिए 15 किलोमीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े कॉरिडोर से जुड़ी योजनाएं घोषित की थीं, लेकिन शासन ने उन्हें मंजूरी नहीं दी। कारण यह बताया गया कि दूसरी ओर की जमीनों को भी योजना में शामिल किया जाए। समस्या यह है कि उस हिस्से की अधिकांश जमीनें मास्टर प्लान में कृषि उपयोग की श्रेणी में आती हैं, जिन पर आवासीय योजनाएं घोषित नहीं की जा सकतीं। इसी वजह से करीब 3 हजार एकड़ जमीन अधर में लटकी हुई है और वहां नगर तथा ग्राम निवेश अभिन्यास की मंजूरी भी नहीं दे रहा है। हालांकि, इन जमीनों के कुछ मालिक अदालत भी पहुंच गए हैं। इनमें नैनोद, रीजलाय, जम्बूडीहब्सी और पालाखेड़ी क्षेत्रों की जमीनें प्रमुख हैं। खास बात यह है कि करीब 100 एकड़ जमीन पर नगर तथा ग्राम निवेश पहले ही अभिन्यास की मंजूरी दे चुका है, जिन्हें प्राधिकरण ने योजना में शामिल कर लिया, लेकिन अब इसे लेकर कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। प्राधिकरण सूत्रों का कहना है कि नई टीपीएस योजनाओं के माध्यम से छोटे आकार के भूखंडों को विकसित करने की योजना है, ताकि निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को भी आवासीय भूखंड मिल सकें। फिलहाल चल रही योजनाओं में छोटे भूखंड उपलब्ध नहीं हैं और जो हैं वे बेहद महंगे हो चुके हैं। उधर, सुपर कॉरिडोर क्षेत्र और अन्य हिस्सों में भी पुरानी और नई टीपीएस योजनाओं पर काम जारी है। इनमें टीपीएस-1, 3, 4-5, 8, 9 और 10 शामिल हैं, जिनमें कुल 1176 हेक्टेयर जमीन शामिल की गई है। इन योजनाओं के अभिन्यास भी पहले ही रोके जा चुके हैं। साथ ही मास्टर प्लान की 45 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण इन योजनाओं के तहत किया जाना है।

संपादकीय | दुनिया में मौसम के बिगड़ते स्वरूप को लेकर चिंता

मौसम की अपनी गति होती है और सामान्य स्थितियों में वह पारिस्थितिकी चक्र को बनाए रखने का एक जरूरी हिस्सा होती है। मगर पिछले कुछ समय से इसके स्वरूप में तेजी से बदलाव दर्ज किया जा रहा है और खासतौर पर बारिश की वजह से होने वाली तबाही की तस्वीर ज्यादा बिगड़ती जा रही है। यों हर वर्ष मानसून के पूरे मौसम में बारिश की वजह से देश के ज्यादातर हिस्से कम या ज्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि बरसात अब बेलगाम हो रही है और तबाही का सिलसिला-सा बनता जा रहा है।

पिछले दिनों उत्तराखंड के धराली और हर्षिल में, फिर जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने और उससे हुई जानमाल की भारी तबाही की जैसी घटनाएं हुई, उन्होंने देश के बाकी हिस्सों के लोगों को भी दहला दिया। अब कश्मीर के कठुआ में भी बादल फटने और भूस्खलन की घटना में सात लोगों की जान चली गई। दूसरी ओर, मुंबई में लगातार तीन दिन की बारिश के बाद हालत यह हो गई, मानो शहर में बाढ़ आ गई हो। वहां कई इलाकों में जलभराव की वजह से जनजीवन पूरी तरह बाधित हो गया, कई जिलों में चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं मराठवाड़ा क्षेत्र में बादल फटने की घटना में नांदेड़ के पांच लोगों के लापता होने की खबर आई।

इसी तरह, हिमाचल प्रदेश के मंडी सहित कई इलाकों में जिस तरह लगातार बार-बार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे समूची स्थानीय आबादी के सामने किसी तरह खुद को बचाने की चुनौती खड़ी हो रही है। यह समझना मुश्किल हो रहा है कि कम या ज्यादा बरसात वाले जिस मानसून को देश की खेती-किसानी के लिए

एक जरूरत के तौर पर देखा जाता था, अब वह कई राज्यों में व्यापक तबाही का कारण क्यों बन रहा है। कई इलाकों में अब बारिश के समांतर बादल फटने की घटना में भी इतनी तेजी से बढ़ोतरी क्यों देखी जा रही है?

दूसरी ओर, कई शहरों में एक-दो घंटे की बरसात में ही सब कुछ ठहर-सा जाता है और चारों ओर बाढ़ का दृश्य बन जाता है। यह निश्चित रूप से अनियोजित शहरी विकास का नतीजा है, जहां बहुत अच्छी सड़कें तो बना दी जाती हैं, लेकिन पानी के निकास का उचित और पर्याप्त इंतजाम नहीं किया जाता है। नतीजतन, दिल्ली जैसे महानगर का बड़ा हिस्सा कुछ देर की घनघोर बरसात में ही जलभराव, सड़क जाम से त्रस्त हो जाता है और पेड़ों के गिरने से होने वाले जानमाल के नुकसान की अनेक घटनाएं सामने आती हैं।

हालांकि समूची दुनिया में मौसम के बिगड़ते स्वरूप को लेकर चिंता जताई जा रही है और इसे वैश्विक तापमान का नतीजा माना जा रहा है। इस मसले पर वैज्ञानिक अध्ययनों में बारिश के बेलगाम होने और उससे तबाही की मूल वजहों की खोज की जा सकेगी और फिर उसी मुताबिक उसका सामना करने के उपाय भी ढूंढे जाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं को शायद रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उससे बचाव के उचित इंतजाम किए जाएं, तो तबाही से जानमाल के नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है।

विडंबना यह है कि पहाड़ी इलाकों में नदियों के किनारे आबादी बस जाती है, पर्यटन के लिहाज से बड़े होटल बना लिए जाते हैं, लेकिन इस बात का खयाल रखना जरूरी नहीं समझा जाता कि अगर कभी मौसम की वजह से नदी का रुख बिगड़ा तो उससे बचना कैसे मुमकिन होगा। जरूरत इस बात की है कि प्रकृति और मौसम के चक्र को लेकर एक गंभीर समझ बनाई जाए और उसी अनुकूल जीवनशैली को विकसित किया जाए।

बारिश तो खूब हुई लेकिन चिपचिपी गर्मी ने छकाया

नई दिल्ली, एजेंसी।
दिल्ली में इस बार का मॉनसून जमकर बरस रहा है। आंकड़ों की मानें तो 1901 के बाद से ये दिल्ली का 18वां सबसे बरसाती मॉनसून है। 19 अगस्त तक राजधानी में 524 मिमी बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 40प्रतिशत ज्यादा है। लेकिन बारिश ही नहीं, इस बार की उमस भरी गर्मी ने भी दिल्लीवालों को खूब परेशान किया है। सड़कों पर पानी, हवा में नमी और बढ़ती बीमारियों ने इस मॉनसून को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

हिंदुस्तान टाइम्स के एनालिसिस के मुताबिक, यह दिल्ली का पिछले 53 सालों में दूसरा सबसे उमस भरा मॉनसून है। खासकर बीते हफ्ते की नमी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1 जून से 18 अगस्त तक दिल्ली में औसत रिलेटिव ह्यूमिडिटी 76.5प्रतिशत रही, जो 2008 के 78.1प्रतिशत के बाद दूसरा सबसे ऊंचा आंकड़ा है। यह दिल्ली के सामान्य मॉनसून की नमी (1991-2020 का औसत 67.2 प्रतिशत) से कहीं ज्यादा है। सबसे

दिलचस्प बात यह है कि अगस्त के पिछले पांच दिन (14-18 अगस्त) सबसे ज्यादा उमस भरे रहे, जहां औसत नमी 89.2प्रतिशत तक पहुंच गई। यह 1991-2020 के औसत से 1.14 गुना ज्यादा है।

इस मॉनसून की उमस का सबसे बड़ा कारण जून और जुलाई रहे। जून में औसत नमी 1973 के बाद तीसरे नंबर पर थी, जबकि जुलाई में दूसरे नंबर पर। अगस्त के पहले 18 दिनों में यह दसवें स्थान पर रही, लेकिन 14-18 अगस्त की उमस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आंकड़ों के मुताबिक, जून में नमी सामान्य से 1.23 गुना, जुलाई में 1.12 गुना और अगस्त में 1.05 गुना ज्यादा रही।

जुलाई और अगस्त दिल्ली के सबसे बरसाती महीने हैं और इस बार भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जुलाई में सिर्फ 8 दिन और अगस्त में अब तक सिर्फ 4 दिन बिना बारिश के रहे। बारिश के साथ नमी बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि हवा में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इस बार दिल्ली में उमस का यह तूफान कई कारणों से आया। जून में भले ही दिल्ली में 19 दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में मॉनसून के जल्दी आने से नमी का प्रवाह दिल्ली की ओर बढ़ा। जून के तीसरे हफ्ते तक मॉनसून सिस्टम ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे नमी बढ़ी, हालांकि दिल्ली में मॉनसून 29 जून को ही पहुंचा।

जुलाई और अगस्त में तो बारिश ने जैसे दिल्ली को अपना घर बना लिया। बारिश के दिनों में तापमान गिरता है, लेकिन जब बारिश हल्की होती है या नहीं होती, तब हवा में बची नमी उमस बढ़ाती है। यह इसलिए, क्योंकि ज्यादा नमी शरीर के पसीने को सूखने से रोकती है, जिससे गर्मी और उमस का डबल अटैक होता है। इस चिपचिपी गर्मी ने दिल्लीवालों की सेहत पर भी असर डाला है। ज्यादा नमी के कारण सांस लेने में दिक्कत, त्वचा की समस्याएं और वायरल इंफेक्शन के मामले बढ़े हैं। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है।

एलजी सक्सेना के दिए एक आदेश पर भड़का जिला बार एसोसिएशन

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के सभी जिला बार एसोसिएशन उपराज्यपाल वीके सक्सेना के उस फैसले पर भड़क गए हैं, जिसमें उन्होंने पुलिस को थानों से ही अदालतों में सबूत पेश करने की अनुमति दे दी थी। इस अधिसूचना को वकीलों, न्यायिक प्रणाली और जनहित के विरुद्ध बताते हुए बार एसोसिएशन ने अपनी समन्वय समिति के माध्यम से राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए उपराज्यपाल द्वारा 13 अगस्त को जारी इस आदेश को वापस लेने के लिए कहा है।

इस बारे में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि राजधानी के सभी बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति की बैठक में, उनके नेताओं ने सर्वसम्मति से उस अधिसूचना का विरोध किया, जिसमें पुलिस के बयान थानों से दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। समिति ने दोहराया, यह (अधिसूचना) सुनवाई प्रक्रिया को पंगु बना देगी और न्याय प्रदान करने में बाधा उत्पन्न करेगी। दिल्ली के जिला न्यायालय बार एसोसिएशन एकजुट हैं और किसी भी परिस्थिति में इस तरह के न्याय-विरोधी उपाय को लागू नहीं होने देंगे। समिति के अतिरिक्त महासचिव तरुण राणा ने कहा कि समिति ने संकल्प लिया है कि सरकार को इस अधिसूचना को वापस लेने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाएगा और संबंधित अधिकारियों को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा जाएगा। समिति ने कहा, यदि निर्धारित समय के भीतर अधिसूचना वापस नहीं ली जाती है, तो दिल्ली के सभी बार एसोसिएशन इसका कड़ा विरोध करेंगे और अगर जरूरी हुआ, तो सड़कों पर उतरने सहित आंदोलन भी शुरू करेंगे। इससे पहले दिल्ली उपराज्यपाल ने पुलिस के कामकाज में तेजी लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सभी 226 पुलिस थानों को पुलिसकर्मियों की गवाही के लिए नामित स्थल घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी थी। इस फैसले के बाद पुलिसकर्मी अदालतों में खुद पेश होने की बजाय अपने थाने से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने का रास्ता साफ हो गया था। इस बारे में जारी बयान के मुताबिक, इस पहल से समय के साथ ही संसाधन और मानवशक्ति की भारी बचत होने की उम्मीद है।

रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले की मां ने बेटे को बताया पशु प्रेमी

नई दिल्ली, एजेंसी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारने वाले शख्स का पता चल चुका है। व्यक्ति गुजरात के राजकोट का है और उसकी उम्र 35 साल है। नाम राजेश भाई खिमजी है। दिल्ली पुलिस ने इस बाबत गुजरात पुलिस से भी संपर्क

किया,फिलहाल तो आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। इस बीच हमलावर की मां से जब मीडियावालों ने सवाल पूछना चाहा तो वो कन्नी काटती नजर आई। उनके चेहरे पर उस वक्त मुस्कान भी थी।

राजकोट में रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले राजेश खिमजी की मां भानुबेन के घर पहुंचकर मीडिया ने उनसे इस घटना के बारे में सवाल पूछा,लेकिन मां ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस दौरान उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मां ने बेटे को पशु प्रेमी बताया है। इसके बाद वह एक ऑटो में सवार होकर निकल गईं। राजकोट में राजेश खिमजी के पड़ोसी से भी बात की। उन्होंने उसे बेहतरीन इंसान और पशु प्रेमी बताया। पड़ोसी ने कहा कि मैं उसे बीते 5-6 सालों से जानता हूं। वह बहुत साधारण और उदार व्यक्ति हैं। पड़ोसी ने कहा कि वह जानवरों से बहुत प्रेम करता है। वो तो गाय को चारा-रोटी खिलाता है और शंकर भगवान का भक्त है। राजेश का छोटा भाई भी शांत है और आजतक कोई झगड़ा नहीं किया।

बढ़ता हथियारों का खतरनाक खेल

पुलिस की लाठी बनाम अपराधियों की एके-47

नई दिल्ली, एजेंसी।
दिल्ली-एनसीआर में अपराधी अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। पिछले दो सालों में एक दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों की हत्या इस बात का सबूत है कि अपराधी अब न सिर्फ हथियारों से लैस हैं, बल्कि उनके पास असॉल्ट राइफल और विदेशी पिस्तौल जैसे घातक हथियार हैं, जो ज्यादातर अवैध बाजारों से खरीदे जाते हैं। दूसरी ओर पुलिस के पास पुरानी 9द्वद्व पिस्तौल, जर्जर राइफलें और कई बार तो सिर्फ लाठियां ही हैं। आज के अपराधी न सिर्फ स्मार्ट हैं, बल्कि उनके पास हथियारों का ऐसा जखीरा है, जो पुलिस को पसीने छुड़ा देता है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक मामले में 30 जिंदा कारतूसों के साथ एक एके-47 राइफल जब्त की। यह हथियार बिहार के मुंगेर जिले की अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में तैयार किया गया था और इसे महज 2.4 लाख रुपये में बेचा जाना था। इस मामले में पकड़े गए कपिल कुमार ने बताया कि उसने यह राइफल एक प्रॉपर्टी डीलर से खरीदी थी और इसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सक्रिय गिरोहों को सप्लाई करने वाला था। अवैध हथियारों का यह कारोबार अब एनसीआर में तेजी से फैल रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी (क्राइम) देवेश चंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक, बिहार के मुंगेर के अलावा

पश्चिमी यूपी का बुलंदशहर, मध्य प्रदेश का मऊ और अब राजस्थान का डीग क्षेत्र भी नकली हथियार बनाने का गढ़ बन गया है। हैरानी की बात है कि ये घातक हथियार छोटे-छोटे बैकयार्ड वर्कशॉप में बनाए जाते हैं। पुराने लेथ मशीनों और वेल्डिंग उपकरणों के जरिए एके-47 जैसे हथियारों की नकल इतनी आसानी से तैयार की जाती है कि देखकर दंग रह जाएंगे। बार-बार छापेमारी के बावजूद यह धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक, मुंगेर और अन्य क्षेत्रों में बने ये हथियार अब दिल्ली जैसे शहरी केंद्रों में पहुंच रहे हैं, जहां संगठित अपराधी गिरोह इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस साल मई में दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के डीग में अवैध हथियार बनाने और सप्लाई करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। तीन दिन की कार्रवाई में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो दिल्ली-एनसीआर में अपराधियों, खासकर विकास लगरपुरिया गिरोह को हथियार सप्लाई कर रहे थे। जॉइंट पुलिस कमिश्नर (क्राइम) सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इस ऑपरेशन में 11 अवैध हथियार, जिसमें एक राइफल और 10 पिस्तौल शामिल थे, साथ ही 17 जिंदा कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए। इस गिरोह के सरगना मोहम्मद जूबर का नेटवर्क डीग के जंगली इलाकों से संचालित हो रहा था। जूबर के साथ हविंदर सिंह, सोनू सिंह, मोहम्मद मुबीन और शेर मोहम्मद उर्फ शेरू भी पकड़े गए। मुबीन, जो 2013 से हथियार बनाने में प्रशिक्षित था, 12,000 रुपये तक में पिस्तौल बेचता था। हविंदर और सोनू दिल्ली के अपराधी गिरोहों को हथियारों की रीसेलिंग करते थे। दूसरी ओर, एनसीआर में पुलिस की स्थिति चिंताजनक है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा के ज्यादातर पुलिस स्टेशनों के पास एके-47 जैसे हथियार तो दूर, इनके इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी नहीं है। एक रिटायर्ड सीपी ने बताया कि 9द्वद्व पिस्तौल छोटी दूरी के लिए बनाई गई है, जबकि एके-47 जैसी असॉल्ट राइफल सैकड़ों मीटर तक मार कर सकती है।

श्री गणेशाय नमः

राधाकृष्ण

दूध डेयरी

दूध,दही,घी,पनीर,मठ्ठा,बटर,क्रीम,
छाछ मिलने का एकमात्र स्थान

पति बाजार शीतला माता मंदिर के पास
महू जिला इंदौर

दैनिक रणजीत टाइम्स

जिला एवं तहसील स्तर पर
एजेंसी देना है

अपना बायोडाटा सम्पूर्ण विवरण के साथ हमें प्रेषित करें।
सम्पर्क करें

8224951278 :: 9827068888

जन्मदिन की
अग्रिम शुभ सूचना

"रंजीत टाइम्स" में अब आप अपने या
अपने प्रियजनों का जन्मदिन एक दिन पहले ही निशुल्क
प्रकाशित करवा सकते हैं!

बस हमें भेजिएः 1 जन्मदिन मनाने वाले की फोटो

2 उसका पूरा नाम- 3 बधाई देने वाले का नाम जन्मदिन के एक दिन पहले ही
विज्ञापन भेज दें, ताकि समय रहते प्रकाशित किया जा सके।

भेजने का नंबर (Aditya): 8224951278

रंजीत टाइम्स में आपका विज्ञापन पूरी तरह मुफ्त प्रकाशित किया जाएगा!
अपने जज़बातों को शब्द दें – सिर्फ रंजीत टाइम्स के साथ।
टीम रंजीत टाइम्स- "आपका अपना अख़बार, आपकी आवाज़"

रणजीत टाइम्स